

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 05 सितम्बर, 2006

विषय : शासनादेश संख्या:109/XXVII(2)/2006 दिनांक: 29 जून, 2006 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या:109/XXVII(2)/2006 दिनांक: 29 जून, 2006 के द्वारा दिनांक: 01.01.1986 से पूर्व 470-735 के वेतनमान के आशुलिपिकों के दिनांक: 01.01.86 तथा 01.01.96 से वेतनमान पुनरीक्षण के विषय में निर्गत व्यवस्था के विषय में शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ मांगों के द्वारा दिनांक: 01.01.86 के बाद आशुलिपिक के सृजित पदों पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी उक्त शासनादेश के अनुसार वेतनमान के पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है और कतिपय पदधारकों को पुनरीक्षित वेतनमान अपने स्तर से विभागाध्यक्ष के द्वारा ही अनुमन्य कर दिया गया है।

2 इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक: 29 जून, 2006 के द्वारा वेतनमान पुनरीक्षण की व्यवस्था आशुलिपिक के पदों पर कार्यरत/नियुक्त केवल उन पदधारकों के लिए ही अनुमन्य होगी, जो दिनांक 01.01.1986 के पूर्व रु0 470-735 के वेतनमान में सृजित हुए पदों पर नियुक्त हुए हों और उनका वेतनमान दिनांक: 01.01.86 से रु0 1200-2040 तथा दिनांक: 01.01.96 से रु0 4000-6000 के वेतनमान में पुनरीक्षित हुआ हो। शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 के अनुसार वेतनमान पुनरीक्षण के प्रस्तावों पर कार्यवाही तभी की जाय जब वेतनमान रु0 470-735 में पद के सृजन का शासनादेश, या उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने पर दिनांक 01.01.86 एवं दिनांक: 01.01.96 को उक्त पद के वेतनमान के संशोधन के शासनादेश प्रशासनिक विभाग के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी कर दिया

जाय। वेतन निर्धारण एवं किसी प्रकार के एरियर का भुगतान कोषागार द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश के बाद ही किया जाय।

3. यदि उक्त प्रक्रिया के अनुसरण किये बिना ही किन्हीं पदधारकों को विभागाध्यक्ष के आदेश से ही उक्त वेतनमान का पुनरीक्षण कर अवशेष का भुगतान दिया गया हो तो उक्त प्रक्रिया अनियमित मानी जायेगी। यदि बिना वित्त विभाग की सहमति एवं पदों के स्पष्ट उल्लेख के, स्पष्ट शासनादेश निर्गत करवाये, कोई धनराशि आहरित की गयी हो तब उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाय।

4. मा० न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के क्रम में मात्र दिनांक 1.1.86 के पूर्व रु० 470-735 के वेतनमान के पदों हेतु ही यह व्यवस्था लागू की गयी है। दिनांक 1.1.86 के बाद सृजित पद या नियुक्त होने वाले आशुलिपिकों हेतु पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। दिसम्बर, 2004 से इस सर्वग हेतु लागू स्टाफिंग पैटर्न उक्त तिथि पर कुल सृजित पदों के आधार तथा निर्धारित अनुपात में विभाजित किया जाय। मा० न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के क्रम में एक बार रु० 470-735 के वेतनमान के पुनरीक्षण करने का संदर्भ मात्र दिनांक 1.1.86 के पूर्व से उक्त वेतनमान के पदधारकों पर लागू होगा, तथा इसका स्टाफिंग पैटर्न के प्रारम्भिक वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: 145(1) XXVII(7)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
3. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
6. निदेशक, एन०आई०सी० देहरादून।

आज्ञा से
-11/12-06

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव

जाय। वेतन निर्धारण एवं किसी प्रकार के एरिबर का भुगतान कोषागार द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश के बाद ही किया जाय।

3. यदि उक्त प्रक्रिया के अनुसरण किये बिना ही किन्हीं पदधारकों को विभागाध्यक्ष के आदेश से ही उक्त वेतनमान का पुनरीक्षण कर अवशेष का भुगतान दिया गया हो तो उक्त प्रक्रिया अनियमित मानी जायेगी। यदि बिना वित्त विभाग की सहमति एवं पदों के स्पष्ट उल्लेख के, स्पष्ट शासनादेश निर्गत करवाये, कोई धनराशि आहरित की गयी हो तब उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाय।

4. मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के क्रम में मात्र दिनांक: 1.1.86 के पूर्व रू0 470-735 के वेतनमान के पदों हेतु ही यह व्यवस्था लागू की गयी है। दिनांक: 1.1.86 के बाद सृजित पद या नियुक्त होने वाले आशुतिपिकों हेतु पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। दिसम्बर, 2004 से इस सर्वग हेतु लागू स्टाफिंग पैटर्न उक्त तिथि पर कुल सृजित पदों के आधार तथा निर्धारित अनुपात में विभाजित किया जाय। मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के क्रम में एक बार रू0 470-735 के वेतनमान के पुनरीक्षित करने का संदर्भ मात्र दिनांक: 1.1.86 के पूर्व से उक्त वेतनमान के पदधारकों पर लागू होगा, तथा इसका स्टाफिंग पैटर्न के प्रारम्भिक वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: 145(1) XXVII(7)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
3. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।

आज्ञा से
7/1/06

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव